

प्रेषक,

भास्करानन्द,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक ९ जुलाई, 2014

विषय:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-9 के अंतर्गत जलना से तुलेड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.8470 है० भूमि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-8409/ग्यारह-26/2012-13 दि०-27.12.2013 एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं०-6272/रा०प०/2013 दि०-22.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद एवं तहसील अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगाड़ा के पटवारी क्षेत्र जलना के अंतर्गत ग्राम तुलेड़ी के खतौनी खाता सं०-676 की श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खेत सं०-12362, 12356, 12332, 12330, 12335, 12336, 12337, 12303, 12311, 12295, 12246, 957, 881, 880, 877, 876, 869, 213, 498, 518, 659, 771, 765, 766, 1007, 742, 691, 1048, 1054, 661, 1817, 1820, 1659, 1656, 3016, 1753, 1750, 2203, 2898, 9787, 8754, 7235, 826 की 0.7289 है०, खाता खतौनी सं०-620 की श्रेणी 9(3)ग, इजरान खेत सं०-12333, 12331, 12323, 12324, 12325, 12312, 12304, 12290, 12291 की 0.0915 है०, खाता खतौनी सं०-681 की श्रेणी 10(1) रोली के खेत सं०-879, 217, 403, 658, 734 की 0.0089 है०, खाता खतौनी सं०-689 की श्रेणी 10(2) रास्ता के खेत सं०-778 एवं 787 की 0.0111 है०, खाता खतौनी सं०-411 की श्रेणी 10(4) बंजर के खेत सं०-781, 783 की 0.0003 है० इस प्रकार कुल 0.8407 है० भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-02-02 के प्राविधानों के अधीन तथा ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

.....2





- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 8- प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0-436/2011 @SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0-जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-1 से 9 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)

सचिव।

पृ0प0संख्या- 174 /समदिनांकित/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- 4- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)

उप सचिव।